

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 245/2013/जयपुर

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मैट्रो ट्रेडिंग कारपोरेशन
फिल्म कॉलोनी, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 30.09.2015

निर्णय

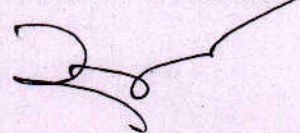
यह अपील सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 169/अपील्स/11/आरवीएटी/जयपुर/एच/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.2011 को वाहन संख्या आरजे 02-जी-5343 को चैक किये जाने पर वाहन में लदा माल कन्साईनमेन्ट पर फार्म एफ के विरुद्ध नासिक से जयपुर के लिए परिवहनित किया जाना पाया गया। परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 दस्तावेजों के साथ नहीं होने के कारण सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया जाना मानकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 6151378 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 76 (2) के अन्तर्गत शास्ति रु. 43,800/- आरोपित कर दी। उक्त आरोपित शास्ति के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2012 पारित किया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 14.5.2009 को वाहन की जांच पर वाहन में लदे माल के साथ वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ

घोषणा प्रपत्र वैट-47 नहीं होने से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर, जवाब के साथ वैट-47 प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 43,800/- आरोपित की, जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम के विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2012 पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि माल परिवहन के समय माल के साथ अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित दस्तावेज नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की थी, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अनुचित रूप से अपास्त किया है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी पी मेटल्स के आधार पर शास्ति को अपास्त किया है, जो गलत है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण के तथ्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तथ्यों से भिन्न है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय को उद्धृत करते हुए आरोपित शास्ति को उचित बताते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल से सम्बन्धित सभी वांछित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब के साथ सभी कारणों का उल्लेख करते हुए घोषणा प्रपत्र वैट-47 संख्या 6151378 दिनांक 15.09.2011 को प्रस्तुत कर दिया गया था, जिससे प्रमाणित होता है कि उसकी करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि वक्त जांच वाहन के साथ बिल, बिल्टी मौजूद थी, जिनमें माल भेजने व पाने वाले का पूर्ण नाम व पता, माल का विवरण एवं माल की कीमत एवं उनके पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या आदि सभी पूर्ण विवरण अंकित था। उन्होंने शासन सचिव वित्त (राजस्व)के पत्र क्रमांक एफ.12(15) वित्त/ कर/2008/पार्ट-3 दिनांक 30.8.2008 को हवाला देते हुए बताया कि उक्त परिपत्र के आधार पर भी परिवहन के दौरान वैट-47 एवं 49 साथ नहीं होने पर भी उनके विरुद्ध शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती थी। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान



उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट-2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित निर्णयों को आधार बनाते हुए अभिवाक् किया कि उक्त दोनों निर्णयों में राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि वक्त जांच Scientific Laboratory Glassware वाहन में भरा हुआ थो, जिसको कन्साईनमेन्ट पर फार्म एफ के विरुद्ध नासिक से जयपुर के लिए परिवहनित किया जा रहा था। वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 नहीं पाया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने माल परिवहन के समय उसके साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 होना आज्ञापक माना है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 नहीं होने के कारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 संख्या 6151378 पेश किया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 43,800/- आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2012 पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया जाना समीचीन होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट-2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the



reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

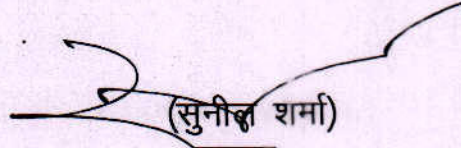
"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2012 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य